सान्ध्य हिन्दी दैनिक जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष – 02 अंक – 325 जौनपुर, गुरूवार, 22 अगस्त 2024 सान्ध्य दैनिक (संस्करण) पेज – 4 मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

13 आईएएस अधिकारी हुए इधर से उधर

लखनऊ, संवाददाता। देश सरकार ने बुधवार को 13 आईएएस अफसरों की जिम्मेदारियों में बदलाव कर दिया। प्रतीक्षा में चल रहीं मिनिष्ती एस को वित्त विभाग में सचिव बनाया गया है। आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और वहां की संभागीय खाद्य नियंत्रक अनिता यादव को प्रतीक्षारत कर दिया गया है। प्रतीक्षारत चल रहे के. विजयेंद्र पांडियन को आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, आयुक्त एवं निदेशक हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड, स्टेट यार्न कंपनी लिमिटेड, सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड और उत्तर प्रदेश वित्त निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। ग्रेटर नोएडा की एसीईओ अन्नपूर्णा गर्ग को नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग में विशेष सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।गोंडा की सीडीओ एम. अरून्मोली को आगरा विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष (वीसी) बनाया गया है। अलीगढ़ की सीडीओ व वहां की संभागीय खाद्य नियंत्रक आकांक्षा राणा को विशेष कार्याधिकारी, कुंभ मेला प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी गई। बहराइच की सीडीओ राम्या आर को विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ के संयुक्त प्रबंध निदेशक मुकेश चंद्र को बहराईच का सीडीओ, बुलंदशहर की संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉ. दिव्या मिश्रा को प्रतापगढ़ का सीडीओ और कानपुर नगर की संयुक्त मजिस्ट्रेट प्रखर कुमार सिंह को अलीगढ़ का सीडीओ बनाया गया है।

आरक्षण से कोई खिलवाड़ न करें विपक्षी दल – मायावती

लखनऊ, संवाददाता। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि एससी–एसटी के साथ ओबीसी समाज को भी मिला आरक्षण का संवैधानिक हक डॉ. अंबेडकर के अनवरत प्रयासों का नतीजा है, जिसकी अनिवार्यता और संवेदनशीलता को भाजपा, कांग्रेस व अन्य पार्टियां समझकर कोई खिलवाड़ न करें। बुधवार को सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा, कांग्रेस आदि दल आरक्षण के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और इसे निष्प्रभावी बनाते हुए खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एससी–एसटी आरक्षण में उप–वर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर इन वर्गों में आक्रोश है। इन वर्गों के द्वारा आज भारत बंद के तहत सरकार को ज्ञापन देकर संविधान संशोधन के जरिए आरक्षण में हुए बदलाव को खत्म करने मांग की जा रही है। इसका बसपा ने भी समर्थन किया है और बंद में बिना किसी हिंसा के अनुशासित व शांतिपूर्ण तरीके से शामिल होने की अपील की है।

हिंदू भारत की सुरक्षा, एकता और एकाग्रता की गारंटी - योगी

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को दिवंगत कल्याण सिंह की तृतीय पुण्यतिथि पर आयोजित शहिंदू गौरव दिवसश के दूसरे संस्करण के कार्यक्रम में शाामिल हुए। सीएम योगी ने बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदू भारत की सुरक्षा की गारंटी है। सीएम योगी ने कहा कि आज जब हम लोग बाबूजी की तीसरी पुण्यतिथि को शहिंदू गौरव दिवसश के रूप में मना रहे हैं, तो हमें हिंदू एकता के महत्व को समझना पड़ेगा। हिंदू कोई जाति, मत और मजहब नहीं है। यह किसी संकीर्ण दायरे का माध्यम नहीं है। यह भारत की सुरक्षा, एकता और एकाग्रता की गारंटी है। याद रखना जब तक भारत का मूल सनातन हिंदू समाज मजबूत है, भारत की एकता और अखंडता को दुनिया की कोई ताकत चुनौती नहीं दे सकती। जिस दिन यह एकता खंडित होगी, उस दिन भारत को फिरके–फिरके में बांटने की विदेशी साजिशें सफल होती दिखाई देंगी। हमें इन साजिशों को सफल नहीं होने देना है। उन्होंने कहा कि जो लोग आपको बांटने का काम कर रहे हैं, इनके चेहरे, चाल और चरित्र अलग हैं। ये बोलेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ और करेंगे कुछ। जब भी इन्हें अवसर मिला, उत्तर प्रदेश को इन्होंने दंगे की आग में झोंका है। जब भी इन्हें अवसर मिला है, इन्होंने हिंदुओं के नायकों को अपमानित किया है। याद कीजिए 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 में अयोध्या में रामभक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। उस समय की सरकार एक तरफ हिंदू समाज को आपस में बांटने का कार्य कर रही थी, तो दूसरी तरफ रामभक्तों पर गोलियां बरसा रही थी। तब अडिग चट्टान बनकर उनके सामने टकराने वाला व्यक्तित्व श्रद्धेय बाबूजी कल्याण सिंह थे। उन्होंने कहा था कि हम हिंदू समाज को बंटने नहीं देंगे। ये जाति का जहर घोलने वाले भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 की तिथियां भारत के इतिहास में काले अध्याय के रूप में लिखी जाएंगी, जब अयोध्या में निर्ममतापूर्वक रामभक्तों का लहू बहाया गया था। तब भी श्रद्धेय बाबू जी ने ही आवाज मुखर की थी। 6 दिसंबर 1992 को जब केंद्र सरकार का दबाव था कि अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलाई जाए तब बाबूजी ने कहा था कि केंद्र चाहे तो हमारी सरकार बर्खास्त कर दे, नहीं तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन रामभक्तों पर हरगिज गोलियां नहीं चलाई जाएंगी।

यूपी कोर्ट ने सांसद संजय सिंह को दो दशक पुराने मामले में गिरफ्तार करने का दिया आदेश

सुल्तानपुर, संवाददाता। सुल्तानपुर की एक अदालत ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के दो दशक पुराने मामले में पेश न होने पर कड़ी आपत्ति जताई और पुलिस को उन्हें 28 अगस्त को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया। 13 अगस्त को सिंह, सपा नेता अनूप सांडा और चार अन्य के खिलाफ गैर–जमानती वारंट जारी किया गया था, जिसकी सुनवाई मंगलवार को होनी थी। हालांकि आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि अदालत ने पुलिस को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर 28 अगस्त तक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। छह आरोपियों की ओर से पेश हुए मदन सिंह ने कहा कि सिंह और सांडा की जमानत याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में दायर की गई है, जिस पर 22 अगस्त को सुनवाई होगी। यह मामला 19 जून 2001 का है, जब शहर के सब्जी मंडी क्षेत्र के पास एक ओवरब्रिज के पास पूर्व सपा विधायक अनूप सांडा के नेतृत्व में खराब बिजली आपूर्ति को लेकर प्रदर्शन किया गया था। इस प्रदर्शन में संजय सिंह के साथ पूर्व पार्षद कमल श्रीवास्तव, विजय कुमार, संतोष और सुभाष चौधरी ने हिस्सा लिया था।

राजनाथ सिंह की अमेरिका यात्रा से रणनीतिक साझेदारी को मिलेगी मजबूती

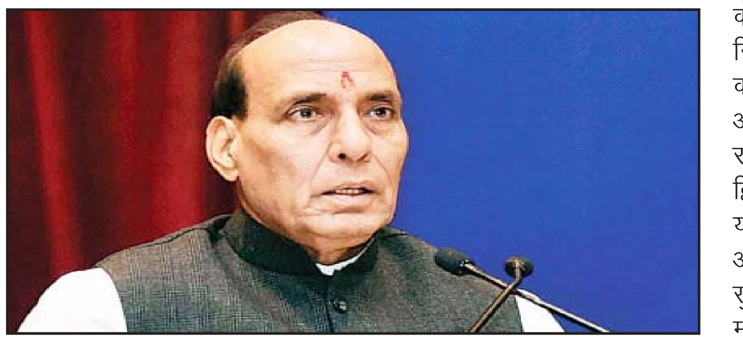

नई दिल्ली, एजेंसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका की आधिकारिक यात्रा करेंगे। उनकी यह यात्रा भारत–अमेरिका रक्षा संबंध को लेकर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इस यात्रा से भारत व अमेरिका की वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूती मिलेगी। इससे पहले मंगलवार को राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री के साथ एक अहम मुलाकात की थी। बुधवार को अमेरिका यात्रा के विषय में आधिकारिक जानकारी देते हुए रक्षा मंत्रालय ने बताया कि राजनाथ सिंह 23 से 26 अगस्त तक अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। राजनाथ सिंह की यह यात्रा अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के निमंत्रण पर हो रही है। 23 अगस्त को अमेरिका पहुंचने के बाद वे यहां अपने अमेरिकी समकक्ष व अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। राजनाथ सिंह यहां राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के सहायक जेक सुलिवन से भी वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अमेरिका में मौजूदा और भविष्य के रक्षा सहयोग के बारे में रक्षा उद्योग के साथ एक उच्च स्तरीय गोलमेज बैठक आयोजित की जानी है। इस गोलमेज बैठक की अध्यक्षता भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही करेंगे। अमेरिका की अपनी इस यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात और बातचीत करेंगे।

मलेशिया के प्रधानमंत्री ने की राहुल गांधी से मुलाकात

नई दिल्ली, एजेंसी। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की. इंडिया टुडे टीवी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में इब्राहिम ने गांधी परिवार को पारिवारिक मित्र बताया। इब्राहिम भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं, जो 2022 में प्रधान मंत्री बनने के बाद उनकी पहली यात्रा है। राहुल गांधी के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बात करते हुए इब्राहिम ने कहा, ष्यह एक अच्छी मुलाकात थी। वे (गांधी परिवार) पारिवारिक मित्र हैं। मैंने उनसे (राहुल) कहा कि हमें सभी पक्षों से जुड़ने की जरूरत है क्योंकि भारत एक महत्वपूर्ण भागीदार है। गौरतलब है कि इब्राहिम ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। मुलाकात के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने बीजेपी नेता से कुछ चिंताएं व्यक्त कीं। उन्होंने एक निजी मीडिया से बात करते हुए कहा कि कूटनीति केवल मामूली बातों के बारे में नहीं है, बल्कि उन मुद्दों को उठाना भी है जो हमारे दिल के करीब हैं। ये मुद्दे न केवल लोकतांत्रिक बदलाव, स्वतंत्रता, अधिकारों, लोगों के आर्थिक विकास से संबंधित हैं, बल्कि जातीय अल्पसंख्यकों से भी संबंधित हैं। साक्षात्कार के दौरान, उन्होंने यह भी कहा कि मलेशिया को भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के सामने आने वाले मुद्दों पर चिंताएँ हैं। उन्होंने कहा, जिस तरह भारत को मलेशिया से सवाल करने का अधिकार है, उसी तरह हम भी धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों की चिंताओं के संबंध में सवाल उठा सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई दिल्ली अल्पसंख्यकों के सामने आने वाले मुद्दों से निपटने में अपनी उचित भूमिका निभाती रहेगी। मैं इस तथ्य से इनकार नहीं करूंगा कि आपको अल्पसंख्यकों या धार्मिक भावनाओं को प्रभावित करने वाले कुछ गंभीर मुद्दों से भी जूझना पड़ता है।

लेकिन हमारी आशा है कि भारत अपनी उचित भूमिका निभाता रहेगा क्योंकि मैंने प्रधान मंत्री (नरेंद्र) मोदी से कहा था कि ये वे वर्ष थे जब नेहरू और झोउ एनलाई और सुकर्णो और न्येरेरे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ ग्लोबल साउथ के लिए खड़े थे और यह सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष करें कि हम पहचानें कि मानवता क्या है, स्वतंत्रता क्या है और पुरुषों और महिलाओं की गरिमा क्या है।

केंद्र सरकार आरक्षण के खिलाफ, नीतीश कुमार थके हुए सीएम हैं - तेजस्वी यादव

पटना। आरक्षण के मुद्दे पर देशभर में आंदोलन चल रहा है। इसे लेकर बुधवार को भारत बंद का भी आह्वान किया गया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि हम लगातार कहते आ रहे हैं कि केंद्र सरकार आरक्षण के खिलाफ है और अब इसकी तस्वीर भी सामने आ रही है, आज हमने उसी का विरोध किया है। इस दौरान तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ–साथ चिराग पासवान पर भी निशाना साधा और कहा कि क्या ये लोग और इनके परिवार के अन्य सदस्य आरक्षण का लाभ नहीं ले रहे हैं। सिर्फ बड़ी–बड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा, हमें हकीकत की बात करनी होगी। बिहार में बढ़ते अपराध पर उन्होंने कहा कि हर दिन बिहार के अलग–अलग जिलों में अपराधी बिना किसी डर के खुलेआम अपराध कर रहे हैं। कल का ही उदाहरण लें, हाजीपुर में एक जनप्रतिनिधि को हथियारबंद अपराधियों ने एक–दो नहीं बल्कि पांच गोलियां मारकर हत्या कर दी। हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं कि क्या यही आपका सुशासन है। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री थक चुके हैं और अब उनमें सरकार चलाने की क्षमता नहीं रही। चंद अधिकारी और अपराधी वर्ग के लोग सरकार चला रहे हैं।

बता दें कि अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित और आदिवासी संगठनों ने बुधवार को श्भारत बंदश का आयोजन किया। यूपी में सपा, बसपा, आजाद पार्टी समेत तमाम संगठनों ने भारत बंद को अपना समर्थन दिया। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर बसपा कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर प्रतिमा के पास विरोध–प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके हाथों में आरक्षण बचाने को लेकर बैनर–पोस्टर भी देखने को मिला। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं।

बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं भारत बंद जैसे जन आंदोलन – अखिलेश यादव

लखनऊ, संवाददाता। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने एक दिवसीय भारत बंद बुलाया है। दलित और आदिवासी संगठनों के भारत बंद को बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी का समर्थन है। इसी बीच सपा मुखिया अखिलेश ने कहा कि जन–आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि आरक्षण की रक्षा के लिए जन–आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। ये शोषित–वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के खिलाफ जन शक्ति का एक कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार होता है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने पहले ही आगाह किया था कि संविधान तभी कारगर साबित होगा जब उसको लागू करने वालों की मंशा सही होगी। सत्तासीन सरकारें ही जब धोखाधड़ी, घपलों–घोटालों से संविधान और संविधान द्वारा दिये गये अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेंगी तो जनता को सड़कों पर उतरना ही होगा। जन–आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं। उधर, प्रशासन इस बंद को लेकर काफी चौकसी बरत रहा है और संवेदनशील जिलों मे अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। सरकार की तरफ से प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। कई जगह जिलाधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी तरह की हिंसा ना हो और ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक निपट जाए। गौरतलब हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।

पीयूष ने ई–कामर्स कंपनियों द्वारा कीमत निर्धारण में गड़बड़ी को लेकर जताई चिंता

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को ई–कॉमर्स कंपनियों द्वारा वस्तुओं के मूल्य निर्धारण करने के तरीके को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इससे लंबी अवधि में छोटे दुकानदारों और बाजार को नुकसान हो सकता है। एक इवेंट में श्नेट इम्पैक्ट ऑफ ई–कॉमर्स ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड कंज्यूमर वेलफेयर इन इंडियाश नाम की रिपोर्ट को लॉन्च करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब अमेजन कहता है कि हम भारत में अरबों डॉलर का निवेश करने जा रहे हैं, तो हम सभी इस बात की खुशी मनाते हैं, लेकिन हम इसके पीछे की कहानी को भूल जाते हैं कि यह अरबों डॉलर कोई सेवा कार्य या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए नहीं है। मंत्री ने आगे कहा कि ये अरबों डॉलर केवल उस नुकसान की भरपाई के लिए है कि कंपनी की भारतीय इकाई ने इस वर्ष में किया है। अगर कोई कंपनी साल में 6,000 करोड़ रुपये का नुकसान कर रही है, तो इससे मूल्य निर्धारण में गड़बड़ी जैसी गंध नहीं आती है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के नुकसान से ऐसा लगता है कि कंपनी मूल्य निर्धारण में गड़बड़ी कर रही है, जिससे कि छोटे दुकानदार बिजनेस से बाहर हो जाएं। गोयल ने कहा कि ई–कॉमर्स 27 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के साथ तेज गति से आगे बढ़ रहा है।

संशोधन वक्त और वक्फ दोनों की जरूरत, जेपीसी में खुले दिल से होगा विचार - मुख्तार अब्बास नकवी

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में समाप्त हुए संसद सत्र के दौरान पेश किए गए वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को लेकर राजनीतिक हलचल एक बार फिर बढ़ने जा रही है। वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर विस्तार से विचार विमर्श करने के लिए बनाई गई जेपीसी की पहली बैठक गुरुवार 22 अगस्त को होने जा रही है। भाजपा के लिए यह संशोधन विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है और पार्टी के रणनीतिकार चाहते हैं कि इस विधेयक को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पारित करवा लिया जाए। हालांकि अब बहुत कुछ जेपीसी की रिपोर्ट पर भी निर्भर हो गया है। भाजपा को वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर विरोधी दलों को ही नहीं साधना है बल्कि चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान जैसे सहयोगियों को भी बिल के समर्थन में वोट करने के लिए मनाना है। आईएएनएस के साथ खास बातचीत करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इन तमाम सवालों पर खुल कर अपनी बात कहते हुए कहा कि संशोधन वक्त और वक्फ दोनों की जरूरत है और जेपीसी की बैठकों में इस पर खुले दिल से विचार होगा। आईएएनएस से बातचीत में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वह तो पहले ही कह चुके हैं कि इस पूरी व्यवस्था (वक्फ बोर्ड की) को टच मी नॉट की सनक, सियासत और सोच से बाहर निकलना होगा। वक्फ व्यवस्था को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए ही सरकार यह विधेयक लेकर आई है।सहयोगियों की तरफ से भी उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ कानूनों में कोई पहली बार संशोधन नहीं किया जा रहा है, पहले भी इसमें संशोधन किए गए हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में भी संशोधन हुए हैं और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान भी संशोधन हुए हैं। सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयक पर बहस हो, चर्चा हो, इसकी बारीकियों का विश्लेषण हो, इसलिए ही तो इस विधेयक को जेपीसी को भेजा गया है। जेपीसी एक संवैधानिक व्यवस्था है और इसकी बैठकों में खुले दिल से इस विधेयक पर चर्चा होगी। जिस राजनीतिक दल का जो भी तर्क होगा, वो जेपीसी की बैठकों में आएगा, उस पर चर्चा होगी और सब कुछ जेपीसी की रिपोर्ट में भी आएगा। उन्होंने इस विधेयक को कम्युनल रंग देने की कोशिशों का विरोध करते हुए कहा कि इस विधेयक को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कंफ्यूजन के हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है।

संपादकीय

प्रेरित कर रहा संकट

कई साल पहले, जब सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने में पूरी तरह से जुटी हुई थी, जिसने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक संघर्ष की धमकी दी थी, मैंने लिखा था "आज, यह मुद्दा, जो सत्तारूढ़ पार्टी के लिए काफी परिचित है, असम और देश के सभी हिस्सों में, खासकर शहरी इलाकों में नियंत्रण से बाहर हो गया है। मुसलमानों को अवैध प्रवासियों की श्रेणी में अलग–थलग करने की कोशिश उल्टी पड़ गई है। दंगे, आंदोलन, हड़ताल और हिंसा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यह मुसलमानों द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन नहीं है। यह एक स्वतःस्फूर्त विस्फोट है जिसमें सभी समुदाय अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा कोई संकेत नहीं दिखता कि इसका मास्टरमाइंड या नेतृत्व किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा किया जा रहा है। अन्य दलों के राजनीतिक नेता आंदोलनकारियों का अनुसरण करते दिखते हैं।" बांग्लादेश में हुए दंगों ने, जिसने अवामी लीग और अडिग शेख हसीना को सत्ता से बाहर कर दिया, एक बार फिर युवाओं की ताकत और अन्याय और अन्याय को बर्दाश्त न कर पाने की उनकी अक्षमता, शीर्ष पर असत्य के प्रति उनके प्रबल प्रतिरोध, एक ऐसे शासन को स्वीकार करने की उनकी अनिच्छा को याद दिलाता है, जो उन्हें लगता है कि भ्रष्टाचार से भरा हुआ है और एक अधीर युवा पीढ़ी की वास्तविक समस्याओं के प्रति असंवेदनशील है। यह इस तथ्य को भी उजागर करता है कि शासन करने वालों और महत्वाकांक्षी युवाओं के बीच पीढ़ी का अंतर दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह केवल बांग्लादेश तक ही सीमित नहीं है। 2022 में, श्रीलंका में अरागालय आंदोलन ने राजपक्षे के आधिपत्य को समाप्त होते देखा। बांग्लादेश का आंदोलन श्रीलंका के आंदोलन से काफी मिलता–जुलता था, सिवाय इसके कि शेख हसीना सरकार ने शुरू में इसे बेरहमी से दबाने का प्रयास किया था। सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन आंदोलन तब तक मजबूत होता रहा जब तक कि बांग्लादेश की सेना ने यह फैसला नहीं कर लिया कि अब बहुत हो गया और हत्याएं बंद होनी चाहिए। श्रीलंका में हिंसा कम थी और पुलिस प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने में अनिच्छुक थी। दो आपातकाल घोषित किए गए। राजपक्षे ने ईश्वरीय मदद भी मांगी। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के निजी ओझा को मंत्रमुग्ध पानी की बोतलें लेकर प्रदर्शन स्थल पर भेजा गया। उसी समय, महिंदा राजपक्षे की अनुराधापुरा में महाबोधि स्थल पर आशीर्वाद लेने की यात्रा को भी आक्रोशपूर्ण विरोध का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश की तरह, श्रीलंका में भी शासक के महल पर छापा मारा गया और लूटपाट की गई, और उसे मालदीव भागना पड़ा। इसी तरह, हसीना के महल गणभवन को बेकाबू भीड़ ने तबाह कर दिया, और उसे बहुत कम समय में सेना द्वारा बचाकर भारत लाया गया। गोटाबाया को श्रीलंका लौटने की अनुमति दी गई, जहां वह गुमनामी में एक गैर–राजनीतिक जीवन जी रहे हैं। हसीना अभी भी भारत में हैंय उनका भविष्य अनिश्चित है। वर्तमान में उन्हें अपने देश में नफरत का सामना करना पड़ रहा है, और उनकी वापसी और न्यायिक परीक्षण के लिए जोरदार आवाज उठ रही है। आंदोलनकारियों द्वारा बांग्लादेश और श्रीलंका के आंदोलन के बीच समानताएं भी खींची गई हैं। कोलंबो से जूम कॉल पर बोलते हुए, इंटर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फेडरेशन के नेता मधुशन चंद्रजीत ने हाल ही में कहा, ष्हमने भी इसी तरह का रास्ता अपनाया है। 2022 में, श्रीलंका की जनता ने नस्लवादी तानाशाह गोटाबाया राजपक्षे के अत्याचारी शासन को हटा दिया।ष श्रीलंका का आंदोलन एक गंभीर आर्थिक संकट के मद्देनजर हुआ। जहाँ श्रीलंका भारी बाहरी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था, वहीं बांग्लादेश का कर्ज स्तर जीडीपी का लगभग 40 प्रतिशत है। बांग्लादेश चार साल से प्रति व्यक्ति जीडीपी में भारत से आगे चल रहा है। बांग्लादेश में आधिकारिक बेरोजगारी दर 2022 में 4.30 प्रतिशत से घटकर 2023 में 4.20 प्रतिशत हो गई, लेकिन युवा बेरोजगारी उच्च बनी रही। रेडीमेड कपड़ों के वैश्विक बाजार में, यूरोपीय और अमेरिकी कोटा प्रणाली को हटाने के बाद बांग्लादेश भारत से आगे निकल गया। फिर भी, लोग, विशेष रूप से युवा, असंतुष्ट थे और विद्रोह कर रहे थे। कहा जाता है कि इसकी शुरुआत पाकिस्तान से आजादी के लिए लड़ने वाले मुक्ति वाहिनी के सैनिकों के बच्चों और नाती–नातिनों के लिए कोटा प्रणाली की शुरुआत से हुई थी। प्रतिरोध के बाद, 2018 में इस कोटे को छोड़ दिया गया था, लेकिन बांग्लादेश की अदालतों ने इसे कमजोर रूप में फिर से लागू करने का विकल्प चुना।

कोई आश्चर्य नहीं कि विद्रोह के बाद, मुख्य न्यायाधीश को भी इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। शायद समृद्धि के आँकड़े – प्रति व्यक्ति जीडीपी और एक अच्छी राजकोषीय स्थिति – वास्तविक क्षेत्र की स्थिति के साथ प्रतिध्वनित नहीं हुए, जैसा कि युवाओं ने इसे माना। सरकारी आँकड़ों ने शायद जोन रॉबिन्सन द्वारा ष्छिपी हुई बेरोजगारीष कहे जाने वाले को सरकारी रोजगार के आँकड़ों में आकस्मिक श्रमिकों और आधे–अधूरे खेतिहर मजदूरों को शामिल करके छिपाया। श्रीलंका और बांग्लादेश ही सत्तावाद के खिलाफ लोकप्रिय विद्रोह के एकमात्र उदाहरण नहीं हैं। अरब स्प्रिंग ने उपनिवेशवाद के बाद से मध्य पूर्व में सबसे बड़ा परिवर्तन किया, जैसा कि ए मुराद अगडेमिर ने अपनी 2016 की किताब, द अरब स्प्रिंग एंड इजराइल्स रिलेशंस विद इजिप्ट में लिखा है।

पीएम द्वारा धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की बात

आदित्य

दिल्ली के लाल किले से 15 अगस्त को अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार भारत के व्यक्तिगत कानूनों को बदलने की दिशा में काम करेगी। उन्होंने कहारू "सांप्रदायिक नागरिक संहिता के 75 वर्षों के बाद, धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की ओर बढ़ना महत्वपूर्ण है। एक बार जब यह बदलाव हो जाएगा, तो यह धार्मिक भेदभाव को खत्म कर देगा और आम नागरिकों द्वारा महसूस की जाने वाली खाई को पाट देगा।" व्यक्तिगत कानून विवाह, तलाक और उत्तराधिकार को नियंत्रित करते हैं। गणतंत्र की स्थापना के समय से ही भाजपा का इस विषय से एक दिलचस्प रिश्ता रहा है। डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने हिंदू व्यक्तिगत कानून में मामूली बदलाव का प्रस्ताव रखा था, खासकर महिलाओं के लिए उत्तराधिकार के सवाल पर। उन्होंने पारंपरिक उत्तराधिकार कानून के दो प्रमुख रूपों की पहचान की और उनमें से एक को महिलाओं के लिए उत्तराधिकार को अधिक न्यायसंगत बनाने के लिए संशोधित किया। यह आरएसएस के राजनीतिक गठन को स्वीकार्य नहीं था। अपने 1951 के घोषणापत्र में, जनसंघ ने हिंदू कोड बिल का विरोध करते हुए कहा कि सामाजिक सुधार ऊपर से नहीं बल्कि समाज से आना चाहिए। 1957 में, इसने कहा कि ऐसे बदलाव तब तक स्वीकार्य नहीं हैं जब तक कि वे प्राचीन संस्कृति में निहित न हों। इसका दावा है कि इसके परिणामस्वरूप ष्उग्र व्यक्तिवादष पनपेगा। 1958 के अपने घोषणापत्र में पार्टी ने लिखा थारू ष्संयुक्त परिवार और अविभाज्य विवाह हिंदू समाज का आधार रहे हैं। इस आधार को बदलने वाले कानून अंततः समाज के विघटन का कारण बनेंगे। इसलिए जनसंघ हिंदू विवाह और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमों को निरस्त करेगा।ष समय के साथ, जब एकल परिवार आम हो गए और समाज में तलाक स्वीकार्य हो गया, तो पार्टी ने बिना कारण बताए इस स्थिति को छोड़ दिया। अपने 1967 के घोषणापत्र में, इसने समान नागरिक संहिता की मांग की। इसके बाद से, यह पार्टी के सभी घोषणापत्रों में दिखाई दिया और इसने अपने मतदाताओं से वादा किया कि अगर वह सत्ता में आई तो इसे लागू करेगी। 2014 और 2019 में भाजपा के पास पूर्ण बहुमत था और दोनों चुनावों में इसने अपने घोषणापत्र में समान नागरिक संहिता का वादा किया था, लेकिन इसने इसे कानून नहीं बनाया या इसका मसौदा तैयार नहीं किया। अब जबकि पार्टी लोकसभा में 240 सीटों पर सिमट गई है, तो वादा फिर से किया गया है, लेकिन इसे पूरा कौन करेगा? श्री मोदी और उनके मंत्रियों द्वारा बनाया गया मसौदा कानून कहां है? बेशक, यह मौजूद नहीं है। इतने सालों में जब से इस देश ने भाजपा सरकार देखी है, तब से कोई मसौदा नहीं बना है, सिर्फ भाषण ही हुए हैं। कोई मसौदा मौजूद नहीं होने का कारण यह है कि इसे हल करना आसान समस्या नहीं है। भाजपा और उसके समर्थकों के लिए, "समान नागरिक संहिता" या "धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता" बहुविवाह के उन्मूलन के लिए एक विकल्प है। लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए, भाजपा को सिर्फ मुसलमानों से ज्यादा लोगों को निशाना बनाना होगा। हिंदू अविभाजित परिवार से जुड़े पहलू ही एकमात्र ऐसे पहलू नहीं हैं जिन्हें हल करना होगा। अधिकांश लोग अनुच्छेद 370 से परिचित हैं, जिसे भाजपा ने लंबे समय तक निशाना बनाया और फिर 2019 में खत्म कर दिया, लेकिन बहुत कम लोगों को अगले अनुच्छेद 371 के बारे में पता होगा, जिसमें कहा गया है कि "नागाओं की धार्मिक या

सामाजिक प्रथाओं (और) नागा प्रथागत कानून और प्रक्रिया के संबंध में संसद का कोई भी अधिनियम३ नागालैंड राज्य पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि नागालैंड की विधानसभा एक प्रस्ताव द्वारा ऐसा निर्णय न ले"। एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता का क्या होगा जो नागा रीति–रिवाजों के खिलाफ जा सकती है? हमें नहीं पता। भाजपा को भी नहीं पता। मार्च 2018 में, नागालैंड बार एसोसिएशन ने नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया था कि राज्य में व्यक्तिगत कानूनों से संबंधित कई केंद्रीय कानून "बुरी तरह से विरोधाभासी हैं और नागा सामाजिक रीति–रिवाजों और प्रथाओं के विपरीत हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ए के प्रावधानों के अलावा, व्यक्तिगत कानून के मामलों में विधायी शक्ति राज्य विधानमंडल के पास निहित है"। उल्लिखित कानून भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925य विशेष विवाह अधिनियम, 1954य भारतीय तलाक अधिनियम, 1869य जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1886य संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890य और पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 थे। बार एसोसिएशन ने कहा कि इन कानूनों को "हमारे अपने राज्य अधिनियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है"। अनुच्छेद 371 में इसी तरह के प्रावधान मिजोस (371 जी) के लिए प्रथागत कानून की रक्षा करते हैं। अब दो बातों पर विचार करने की जरूरत है। पहली बात, प्रधानमंत्री के समान या धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता के आह्वान का विरोध करने या उस पर टिप्पणी करने का तब तक कोई मतलब नहीं है, जब तक कि वे इसका मसौदा तैयार नहीं कर देते। उन्हें इसे दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, भले ही उन पर यह स्पष्ट करने के लिए दबाव न डाला जाए कि उन्होंने 10 साल में जब उनके पास बहुमत था, तब कानून क्यों नहीं लिखा और पारित क्यों नहीं किया। विपक्ष और भाषण से भयभीत समुदायों को तब तक अपनी प्रतिक्रिया रोककर रखनी चाहिए, जब तक कि वे यह न देख लें कि वे बातों के अलावा और क्या पेश करते हैं। दूसरी बात यह विचार करने की है कि वे इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी अब अल्पमत में है। इसी तरह, वक्फ विधेयक क्यों पेश किया गया, जब यह स्पष्ट था कि 240 सीटों वाली भाजपा इसे पारित नहीं करवा सकती और उसके सहयोगी अपने हिंदुत्व एजेंडे को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखते?

जनता का भरोसा कम होते देख दीदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती

विनोद

पश्चिम बंगाल की दबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दर्शकों के सामने झुकने से कोई फायदा नहीं होगा। उन पर लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है और उन्हें नहीं पता कि इस कमी को कैसे रोका जाए। चल रहे विरोध प्रदर्शनों और न्याय की मांग के समर्थन में फुटबॉल डर्बी को स्थगित करना, जिसमें "रात को वापस पाने" की शपथ भी शामिल है, उस अविश्वास का एक संकेत है। ममता बनर्जी सरकार द्वारा दुर्गा पूजा समितियों को 85,000 रुपये का अनुदान देने से इनकार करना भी एक और संकेत है। ये संकेत सरकारी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए भयानक सामूहिक बलात्कार और बर्बर हत्या के प्रति दीदी की प्रतिक्रिया में असंतोष और निराशा के प्रसार और 14–15 अगस्त की रात को पश्चिम बंगाल में 300 स्थानों पर स्वतःस्फूर्त रूप से जुटी हजारों महिलाओं के साथ जनता की एकजुटता के संकेत हैं। फुटबॉल के प्रति जुनून पश्चिम बंगाल में मोहन बागान एथलेटिक क्लब या उसके प्रतिद्वंद्वी ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के प्रति कई पीढ़ियों की वफादारी की महाकाव्य कहानियों का विषय है। दुर्गा पूजा और इस उत्सव को आयोजित करने वाले क्लब और समितियां भी ऐसी ही हैं। जब फुटबॉल क्लब नागरिक– राजनीतिक मुद्दे पर कोई रुख अपनाने का फैसला करते हैं, तो यह डर्बी से भी बड़ी घटना बन जाती है। ममता बनर्जी, जो यह जानती हैं, उन्हें इस संकट से निपटने के लिए अपनी सरकार के फैसलों पर विचार करना चाहिए था, जिसे उन्होंने बहुत गलत तरीके से प्रबंधित किया है। आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बहुत गंभीर रूप से परेशान युवा डॉक्टरों के साथ बैठकर उनके विरोध और उनके डर को समझने के बजाय, राज्य भर के अन्य मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव और नौकरशाही, पुलिस और राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव की घोषणा न करके, ममता बनर्जी ने नीतिगत बदलावों का विकल्प चुना है, कर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद, उन्होंने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को झूठला दिया, जिसने कोलकाता को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहरों में से एक बताया था, जहाँ रिपोर्ट किए गए अपराधों की घटनाएँ तुलनात्मक रूप से सबसे कम थीं। ऐसा करने में, उन्होंने अपनी पसंदीदा वापसी की स्थिति को उजागर किया, एक ऐसी समस्या के लिए एक भयावह पितृसत्तात्मक उपाय जिसने महिलाओं को शिकार के रूप में देखने की प्रचलित विषाक्त मर्दानगी को चुनौती दी। निर्णय और उनकी निष्क्रियता, संभवतः प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को काम पर लौटने के लिए राजी करने और स्वास्थ्य सेवाओं में सामान्य स्थिति बहाल करने के अत्यंत संवेदनशील और निश्चित रूप से अस्थिर कार्य को करने की उनकी क्षमता में आत्मविश्वास की कमी से पैदा हुई है, जो उन्हें बहुत महंगी पड़ेगी। एक सप्ताह से अधिक समय से, न केवल राज्य के सबसे व्यस्ततम आर.जी. कर अस्पताल में, बल्कि पश्चिम बंगाल के अधिकांश सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन और बाहरी रोगी सेवाएँ बाधित हैं।

जनता, जिसका अर्थ है रोगी और उनके परिवार, सेवाओं से जबरन वंचित किए जाने पर अपना असंतोष व्यक्त नहीं कर रहे हैं। यह सहनशीलता कभी भी समाप्त हो सकती है और फिर यह ममता बनर्जी पर निर्भर होगा कि वे इस गंदगी को साफ करें। यह सब जानते हुए भी, विपक्ष के साथ लड़ाई में शामिल होने का उनका फैसला, न्याय की मांग करने वाली महिलाओं की जैविक लामबंदी के लिए उनके समर्थन के रूप में अपनी महिला योद्धाओं के साथ रैली में जाना और उन्हें रात को पुनः प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें प्रदान करना, सूत्रबद्ध है, दूसरे शब्दों में पूर्वानुमानित है। ममता बनर्जी को अभी तक यह समझ में नहीं आया है कि समय उनके खिलाफ है और इसके दो कारण हैं। पहला, 2011 में जब से वे मुख्यमंत्री बनी हैं, समय बीतता जा रहा हैय एक पीढ़ी "परिवर्तन" के वादे और उम्मीद में बड़ी हुई है। "अभया" भी, जैसा कि पीड़िता को जनता ने नाम दिया है, इस विश्वास में बड़ी हुई है कि ममता बनर्जी "परिवर्तन" लाएगी, क्योंकि डॉक्टर प्रशिक्षु और उसके सहयोगी सभी उसी पीढ़ी के हैं। युवा डॉक्टरों द्वारा लंबे समय तक विरोध और स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान एक गहरी अस्वस्थता का हिस्सा हैय सत्ता विरोधी भावना जो हमेशा सभी सत्तारूढ़ दलों और सरकारों को जकड़ लेती है जो एक से अधिक पांच साल के कार्यकाल के लिए सत्ता में बनी रहती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पश्चिम बंगाल में तीन विपक्षी दलों में से कोई भी, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और उसके वामपंथी सहयोगी, बेहतर विकल्प हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उनमें से कोई भी, अब तक, अकेले या संयुक्त रूप से, तृणमूल कांग्रेस को हरा सकता है। हालांकि, इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी संभवतः अपने चरम से आगे निकल चुकी हैं।

मस्तिष्क के डेटा को संरक्षित करने की आवश्यकता

संजय

कोविड महामारी के दौरान दुनिया भर में रिमोट वर्क मानक बन गया, कर्मचारियों की निगरानी तेजी से बढ़ी। कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के वेब ब्राउजिंग इतिहास, ईमेल और वेबकैम की इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगरानी करने के लिए सॉफ्टवेयर तैनात करना शुरू कर दिया – यह सब निरंतर उत्पादकता सुनिश्चित करने के नाम पर। जबकि महामारी का सबसे बुरा दौर हमारे पीछे है, कर्मचारियों की गहन डिजिटल निगरानी जारी है। और मस्तिष्क –निगरानी न्यूरो टेक्नोलॉजी की बढ़ती लोकप्रियता के साथ यह और भी बढ़ने वाला है जिसका उपयोग पहले से ही खनन, वित्त और अन्य उद्योगों में किया जाता है। यह तकनीक मस्तिष्क तरंगों को मापने और किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति के बारे में अनुमान लगाने में सक्षम है, जैसे कि वे थके हुए हैं या ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम के सूचना आयुक्त कार्यालय का अनुमान है कि दशक के अंत तक यह कार्यस्थलों में आम हो जाएगा। तब तक, न्यूरोटेक्नोलॉजी उपकरणों का बाजार 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है। यह ऑस्ट्रेलिया में श्रमिकों के लिए प्रमुख गोपनीयता चिंताएँ प्रस्तुत करता है – विशेष रूप से क्योंकि न्यूरोटेक्नोलॉजी से उत्पन्न कर्मचारी डेटा की सुरक्षा के लिए कोई वर्तमान गोपनीयता कानून प्रावधान नहीं हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे ऑस्ट्रेलियाई सरकार को तत्काल ठीक करना चाहिए क्योंकि वह इस महीने संघीय संसद में गोपनीयता सुधारों का मसौदा पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यूरोटेक्नोलॉजी आपके नजदीकी मस्तिष्क तक पहुँचना न्यूरोटेक्नोलॉजी का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में लंबे समय से किया जाता रहा है। शायद सबसे सफल और प्रसिद्ध उदाहरण कोक्लियर इम्प्लांट हैं, जो सुनने की क्षमता को बहाल कर सकते हैं। लेकिन न्यूरोटेक्नोलॉजी अब तेजी से व्यापक होती जा रही है। यह अधिक परिष्कृत भी होती जा रही है। इस साल की शुरुआत में, टेक अरबपति एलन मस्क की फर्म न्यूरालिंक ने पहले मानव रोगी में अपने कंप्यूटर ब्रेन चिप में से एक को प्रत्यारोपित किया, जिसे ष्टेलीपैथीष के रूप में जाना जाता है। इन चिप्स को लोगों को विचारों को कार्रवाई में बदलने में सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। हाल ही में, मस्क ने खुलासा किया कि दूसरे मानव रोगी के मस्तिष्क में उनकी फर्म की एक चिप प्रत्यारोपित की गई थी। लेकिन अब न्यूरो टेक्नोलॉजी के कम आक्रामक और अधिक सुलभ प्रकार उपलब्ध हैं। ये किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की गतिविधि की निगरानी करने के लिए उसके सिर से जुड़े सेंसर का उपयोग करते हैं। उदाहरणों में स्मार्टकैप्स शामिल हैं, जो कार्यस्थल दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए वास्तविक समय में थकान को मापते हैं, और इमोटिव हेडसेट जो इंटरैक्टिव गेमिंग से लेकर वैज्ञानिक अनुसंधान तक हर चीज के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ।चचसम अगली पीढ़ी के वायरलेस हेडफोन भी विकसित कर रहा है जो मस्तिष्क तरंगों की निगरानी करने में सक्षम हैं। इस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल खनन, वित्त और खेल जैसे उद्योगों में कार्यस्थलों पर पहले से ही किया जा रहा है। डेटा विश्लेषण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ न्यूरोटेक्नोलॉजी का संयोजन नियोक्ताओं को कार्यस्थल में और उसके आसपास कर्मचारियों के व्यवहार के बारे में और भी गहरी जानकारी प्रदान करता है। गोपनीयता की समस्याएँरू न्यूरोटेक्नोलॉजी के कई सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि विकलांग लोगों की सहायता करना। लेकिन यह प्रमुख गोपनीयता संबंधी चिंताएँ भी पैदा करता है, जो कि अधिक कार्यस्थलों द्वारा इस तकनीक को अपनाने के साथ बढ़ने वाली हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के मूड या ऊर्जा के स्तर के आधार पर विज्ञापनों को वैयक्तिकृत करने के लिए मस्तिष्क तरंगों के डेटा को तीसरे पक्ष के साथ साझा किए जाने का जोखिम है। यह न्यूरो डिस्क्रिमिनेशन को भी बढ़ावा दे सकता है।

लेटरल एंट्री पर सरकार का यू–टर्न

अजय

सिविल सेवा में लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर मचे बवाल के तीन दिन बाद ही इस मुद्दे पर मोदी सरकार द्वारा यू–टर्न लेने का मतलब साफ है कि हाल के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष और खासकर कांग्रेस के हाथ संविधान और आरक्षण की वो मास्टर की लग गई है, जो मोदी सरकार की किसी भी पहल की भ्रूण हत्या कर सकती है। लेटरल एंट्री मामले में भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार की नीयत पर यह कहकर सवाल उठाए थे कि बिना आरक्षण प्रावधान से पिछले दरवाजे से यह सीधी भर्ती इस का सूचक है कि मोदी सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है और आरक्षण को न मानना संविधान खत्म करने जैसा है। गौरतलब बात यह है कि मोदी सरकार ने लेटरल भर्तियां 2018 में ही शुरू कर दी थीं। लेकिन तब विपक्ष की ओर से भी इसका खास विरोध नहीं हुआ था, जो अब हो रहा है। सरकार इसका न तो कोई ठोस तोड़ खोज पा रही है और न ही विपक्ष के हमलों का पुरजोर राजनीतिक जवाब दे पा रही है। राहुल गांधी के अलावा खुद एनडीए के दो घटकों 'जद यू' और 'लोक जन शक्ति पार्टी' ने भी इन नियुक्तियों का सार्वजनिक रूप से विरोध कर दिया। हालांकि, सरकार में शामिल एक और घटक टीडीपी ने इसका समर्थन किया। बावजूद इसके सरकार ने संविधान और आरक्षण के मुद्दों को लेकर आसन्न राजनीतिक खतरों को भांपा और अपनी बात पर अड़े रहने की जगह बैक फुट पर जाना ही बेहतर समझा। यह भी साफ हुआ कि एनडीए में लेटरल एंट्री पर एकमत नहीं है। कहने को मोदी कैबिनेट के प्रवक्ता और केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कमजोर पलटवार जरूर किया कि लेटरल एंट्री का विचार सबसे पहले कांग्रेसनीत यूपीए सरकार में ही आया था। लेकिन अब कांग्रेस ही इसका विरोध रही है। दरसअल, मोदी 1.0 व 2.0 के ठीक उलट मोदी 3.0 में सरकार को कोर मुद्दों पर बार– बार बैक फुट पर जाना रहा है। मसलन वक्फ बिल सरकार ने संसद में पेश तो किया लेकिन व्यापक विरोध के चलते उसे जेपीसी के पास भेजना पड़ा। हालांकि कुछ लोग इसके पीछे भी भाजपा की रणनीति देख रहे हैं। इसी तरह समान नागरिक संहिता (जिसे अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सेक्युलर सिविल कोड कह रहे हैं), के मानसून सत्र में संसद में पेश किए जाने की चर्चा थी। लेकिन वह भी नहीं हो पाया। अब लेटरल एंट्री के सवाल पर भी सरकार ने यू टर्न लेकर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। इससे यह आशंका सही साबित हो रही है कि एनडीए गठबंधन की सरकार सत्ता संचालन के पिच पर उस तरह से धुआंधार बल्लेबाजी नहीं कर पाएगी, जैसी कि वो पूर्व के दो कार्यकालों में कर सकी थी। दूसरे कार्यकाल में केवल तीन विवादित कृषि कानूनों का मुद्दा ही ऐसा था, जब मोदी सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। लेकिन अब यह बार बार होता दिख रहा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में लेटरल एंट्री की विधिवत शुरुआत मोदी 1.0 में 2018 में हुई। तब पहली बार 9 विशेषज्ञों को केन्द्र सरकार के अलग–अलग विभागों में अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया। इन नियुक्तियों पर सवाल तो तब भी उठे थे, लेकिन कोई राजनीतिक बवाल नहीं मचा। इन 9 विशेषज्ञों का चयन भी यूपीएससी ने 6077 आवेदनों में से किया था। इसमें किसी तरह के आरक्षण का प्रावधान नहीं था। ये नियुक्तियां 3 से 5 साल तक के लिए की गई थीं। इनका कोई अलग से कैडर नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अनुबंध की अवधि समाप्त होते ही इन्हें अपनी जिम्मेदारियों से हटना था। बीते 6 सालो में हुई लेटरल एंट्रियों के जरिए भर्ती हुए विषय विशेषज्ञो का क्या परफार्मेंस रहा, प्रशासन को और कार्यक्षम बनाने में उनकी क्या भूमिका रही, यह प्रयोग कितना सफल और कितना जरूरी समझा गया, आईएएस के एक सुगठित और जटिल जाल में लेटरल एंट्री छाप अधिकारी कितनी आजादी से काम कर पाए, उनकी काबिलियत का सरकारी तंत्र में कितना सदुपयोग हुआ, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। फिर भी सरकार ने ये भर्तियां जारी रखी हैं, इसका अर्थ यही मानें कि वह इन लेटरल एंट्री नौकरशाहों के काम से संतुष्ट रही होगी। लेकिन तब और अब में राजनीतिक फर्क यह है कि जब लेटरल एंट्री सूत्र पर अमल शुरू हुआ तब इसे सरकार में कारपोरेट मानसिकता की सीधी एंट्री और पूंजीवाद के फैलते जाल के रूप में देखा गया था, जिसकी प्राथमिकताएं लोकसेवक से अलग और एक संस्थान को हर हाल में मुनाफे में चलाने के आग्रह से निर्देशित होती हैं। 'जनसेवा' वहां केवल पैसे के बदले दी जाने वाली 'सर्विस' और तकनीकी गुणवत्ता ग्राहक को संतुष्ट के करने के भाव से तय होती है ताकि उपभोक्ता कंपनी से न सिर्फ जुड़ा रहे बल्कि बार उसकी सेवाएं लेता रहे। जबकि एक लोकसेवक संविधान और चुनी हुई सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। लोक प्रशासन का अपना एक विशाल और बेहद जटिल तंत्र है, जो कई गुणों और दोषों से भरा हुआ है। इसमें भी चंद लोग नवाचारी निकल आते हैं। कई भ्रष्टाचार को ही 'लोकसेवा' मान लेते हैं तो ज्यादातर अपनी गर्दन बचाकर नौकरी करते जाने को ही लोकसेवा मानते हैं। इस तंत्र में प्रतिस्पर्द्धा पेशेवर अथवा गुणवत्ता के बजाए मलाईदार पोस्ट हथियाने और राजनीतिक आकाओ को खुश रखने की ज्यादा होती है। दूसरी तरफ कारपोरेट क्षेत्र से आने वाले विशेषज्ञ तुलनात्मक रूप से ज्यादा आजादी ,कड़ी व्यावसायिक प्रतिस्पर्द्धा और न्यूनतम जवाबदेही के माहौल के काम करने आदी होते हैं। वहां प्रतिस्पर्द्धा अपना 'बेस्ट' देने के आग्रह से ज्यादा संचालित होती हैं। हालांकि, व्यवसायगत चालाकियां और दुरभिसंधियों का बोलबाला वहां भी है, लेकिन मालिक को साधकर काफी कुछ साधा जा सकता है।

सत्र 2023-24 की रोटरी क्लब ऑफ लखनऊ डिस्ट्रिक्ट 3120 की वार्षिक आभार पार्टी का समारोह आयोजित

ROTARY CLUB OF LUCKNOW

ROTARY CLUB OF LUCKNOW
Chartered: 1938
Club ID: 15444
RI DISTRICT: 3120

ROTARY CLUB OF LUCKNOW
Chartered: 1938
Club ID: 15444
RI DISTRICT: 3120
#PeopleofAction #Rotary #TheMagicofRotary

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। रोटरी क्लब ऑफ लखनऊ की सत्र 2023–24 की प्रेसिडेंट संगीता मित्तल ने रोटरी कम्युनिटी सेंटर, निराला नगर में अपने सत्र की थैंक्स गिविंग पार्टी का आयोजन किया, इसमें उन्होंने अपने सत्र की उपलब्धियों के बारे में बताया कि रोटरी क्लब ऑफ लखनऊ को डायमंड क्लब, उनको डायमंड प्रेसिडेंटएक्स व क्लब को 50 से अधिक अवार्ड डिस्ट्रिक्ट से मिले है।उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुनील बंसल का भी आभार व्यक्त किया कि उनके कार्यकाल में डिस्ट्रिक्ट 3120 में और रोटरी क्लब ऑफ लखनऊ ने स्वास्थ्य, एजुकेशन , पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण व अन्य बहुत सराहनीय कार्य किए है और बताया कि वो अपने क्लब की सफलता का जश्न मना रही है और अपने सत्र के उन रोटेरियन सदस्यों को उन्होंने सम्मानित किया जिन्होंने पूरे वर्ष क्लब की गतिविधियों में अपना सहयोग दिया, उनमें प्रमुख क्लब के च्क् सी पी अग्रवाल,च्च् प्रवीण कुमार मित्तल, पीपी अशोक भार्गव , पीपी वाई के गोयल, पीपी नरेश अग्रवाल, पीपी संगीता मारवाहा, पीपी दीपक मारवाहा, अशोक टंडन, विनोद तैलंग, विनोद चांदिरिमानी, निर्मल अग्रवाल, अमिता टंडन, सुभाष विद्यार्थी, आर पी सिंह, डॉ निरुपम मुखर्जी , अंजना अग्रवाल, डॉ एस आर सिंह, एस बी सिंह, गणेश अग्रवाल,, गिरिधर गोपाल, श्याम प्रकाश अग्रवाल, संजय बंसल, पंकज कपूर प्रमुख है। रोटेरियंस की स्पाउस को भी सम्मानित किया गया। स्तुति मित्तल, कर्णिका शजवानी, विभोर अग्रवाल, जतिदर वालिया, सर्वजीत सिंह, मुदित बंसल को न्यू रोटेरियंस व संजय चतुर्वेदी और आर एल पाण्डेय को मीडिया सपोर्ट के अवार्ड से सम्मानित किया गया।पार्टी के बाद डिनर का आयोजन भी किया गया।

प्राथमिक विद्यालय के आस पास लगा कचरों का अम्बार

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जहां एक तरफ सरकार के द्वारा चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान को नगर पंचायत कजगांव मुँह चिढ़ा रहा है बता दे कि उक्त नगर पंचायत कार्यालय के ठीक बगल में स्थित प्राथमिक विद्यालय के अगल–बगल कचरों का अम्बार लगा हुआ है जिसके चलते आस–पास पूरी तरह से नरकीय बना हुआ हैद्यजहां एक तरफ उक्त नगर पंचायत में साफ–सफाई करने के लिए दर्जनों से अधिक सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति कि गयी हैद्य वहीं दूसरी तरफ सफाई कर्मी के द्वारा साफ –सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही हैद्य ऐसी स्थिति में देखा जाए तो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान उक्त नगर पंचायत में पुरी तरह से वहाँ विफल देखने को मिल रहा हैद्य देश के भविष्य कहे जाने वाले नौनिहाल जब विद्यालय पढ़ने आते हैं तो अगल–बगल लगी गन्दगी से विद्यालय के बच्चे भी परेशान रहते हैं सफाई न होने के कारण लोग मच्छरों के प्रकोप से परेशान है तथा लोगों को डेंगू,मलेरिया आदि तमाम घातक बीमारियां होने का डर बना रहता है

प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक अमर बहादुर यादव ने बताया कि इस प्रकार की समस्या के बारे में नगर पंचायत अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी एवं कर्मचारियों को अवगत कराने की बावजूद भी साफ–सफाई नहीं कराया जा रहा हैद्य इस प्रकार के समस्या के प्रति नगर पंचायत अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी व कर्मचारी पूरी तरह से कुम्भकर्णी निद्रा में लीन है।

आगामी विधानसभा उप चुनाव के सभी सीटों पर सपा होगी विजई – लाल बिहारी यादव

Infinix SMART5

अयोध्या। केंद्र व प्रदेश में भाजपा सरकार के गलत नीतियों के चलते जनता त्रस्त हो चुकी है। क्योंकि यह सरकार दबे कुचलें लोगों को परेशान करने मे जुटी हुई है। जिसके चलते भाजपा सरकार का जो हाल इस बार लोकसभा चुनाव में हुआ था वही हाल आगामी विधानसभा उप चुनाव में भी होगा।यह बातें गुरुवार को विरोधी दल विधान परिषद के सदस्य लाल बिहारी यादव मे कही।उन्होंने कहा कि इस सरकार कार्यकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है।इस लूट, हत्या, बलात्कार सहित अन्य आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी हुई है।जिस पर अंकुश लगाने में सरकार विफल दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा उप चुनाव में सपा जरुर विजई होगी।भदरसा मामले पर उन्होंने कहा कि आज जो सरकार द्वारा मुईद के प्रतिष्ठानों पर बुलडोजर चलाने का कार्य किया जा रहा है वह गलत है। पहले आरोपी का डीएनए टेस्ट कराया जाये।जांच के आधार पर यह कार्रवाई होनी चाहिए।परंतु सरकार बिना नोटिस जारी किए ही उसके प्रतिष्ठानों पर बुलडोजर चलाने का कार्य किया जा रहा है।जो न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि अयोध्या लोकसभा चुनाव की तरह ही मिल्कीपुर ही नहीं बल्कि जहां जहां पर विधानसभा में उप चुनाव हों रहा है उसमें सपा ही बिजयी होगी।पत्रकार वार्ता में सपा जिला पारस नाथ यादव,पूर्व सपा एमएलसी लीलावती कुशवाहा,सपा नेत्री सरोज यादव,पूर्व विधायक जय शंकर पांडेय,बीकापुर विधानसभा के प्रत्याशी रहे हाजी फिरोज खान गब्बर, बलराम यादव सहित सपा के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

29 अगस्त को अंडमान में होंगे सम्मानित – डा. एस बी तिवारी.....

मृत्युंजय प्रताप सिंह

विश्व विख्यात देश–विदेश में अनेकों सम्मान से सम्मानित डॉ एस बी तिवारी कल्याण जी 29 अगस्त 2024 को अंडमान निकोबार दीप समूह में सम्मानित किए जाएंगे । बताते चलें कि डॉ एस बी तिवारी कल्याण जी होम्योपैथिक के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है जो लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करने के साथ ही साथ मलेशिया दुबई जैसे देश में भी अंतरराष्ट्रीय सम्मान हासिल कर चुके हैं। वह होम्योपैथिक चिकित्सा द्वारा प्रमाण के साथ प्रस्तुति देकर एक मुकाम

UNIVERSITY OF CYBERJAYA

हासिल करते हुए 25000 से भी अधिक पथरी हजारों डायलिसिस सैकड़ो मोटर न्यूरॉन डिजीज जैसी अनेकों असाध्य बीमारियों को ठीक कर उनकी प्रमाणिक प्रस्तुति भी दे चुके हैं जिनके लेख समय–समय पर प्रकाशित होते रहते हैं। भारतीय होम्योपैथी का परचम दुनिया में लहराने वाले एवं भारतवर्ष का नाम रोशन करने वाले डॉक्टर तिवारी को अंडमान में यह सम्मान निश्चित रूप से चिकित्सा जगत के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। डा तिवारी एक सुप्रसिद्ध चिकित्सक के साथ–साथ समाजसेवी कवि योगी एवं भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी रुचि रखने वाले एक अत्यंत ही विनम्र एवं सरल व्यक्तित्व के धनी है। देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर चुके फिनलैंड सरकार द्वारा बहुत बड़े ऑफर को भी ठुकरा चुके हैं । क्योंकि उन्हें देश सेवा ही अपना मूल समझ में आता है।

रोजगार मेले में 56 को मिली नौकरी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर जिला सेवायोजन कार्यालय जौनपुर के तत्वाधान में मिशन रोजगार अभियान के अन्तर्गत निजी नियोजकों के सहयोग से 22 अगस्त 2024 को 'रोजगार मेला' का आयोजन जिला सेवायोजन कार्यालय कैम्पस जौनपुर में किया गया, जिसमें विभिन्न कम्पनियों के द्वारा कुल 56 बेरोजगार अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न पदों पर किया गया। चयनित अभ्यर्थियों को जिला सेवायोजन अधिकारी ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया, इस अवसर पर जिला सेवायोजन अधिकारी जय प्रकाश पासवान एवं सहायक सेवायोजन अधिकारी शशिकान्त सरोज ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित 'मिशन रोजगार अभियान' के तहत इस मेले का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं ने अपनी योग्यता व क्षमता के अनुरूप प्रतिभाग किया तथा रोजगार भी प्राप्त किया। चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए, भविष्य में जनपद के बेरोजगार अभ्यर्थियों को बताया गया कि रोजगार मेले का आयोजन प्रत्येक माह किया जाता रहेंगा। रोजगार मेला प्रभारी शिवकुमार यादव, रामसिंह मौर्य, जीशान अली, आनन्द भूषण त्रिपाठी, अजय कुमार, चन्दशेखर प्रताप, विजय बहादुर आदि उपस्थित रहें।

धनपतगंज ब्लाक प्रमुख उपचुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशी की जीत

सुल्तानपुर। भाजपा समर्थित प्रत्याशी पार्वती देवी बनी धनपतगंज ब्लाक प्रमुख। 42 वोट बीजेपी और 39 वोट मिले सपा प्रत्याशी ऊषा सिंह को। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। पूर्व मंत्री विनोद सिंह ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में किया था समर्थन का आवाहन। पुलिस ने कसा शिकंजा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मारी बाजी।

जनपदीय माध्यमिक विद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता संपन्न

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैलरी हरिद्वार
vivo X80 | ZEISS
Aug 22, 2024, 09:46

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

रुड़की, हरिद्वार। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैलरी के प्रांगण में जनपद स्तरीय माध्यमिक विद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता संपन्न हुई जिसमें जनपद की विभिन्न ब्लॉक के चयनित खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया अपने प्रदर्शन के दौरान उन्होंने उपस्थित खेल प्रेमियों का मन मोह लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन विद्यालय के प्रधानाचार्य सुबोध नेन ने किया इस अवसर पर उन्होंने प्रतिभागी खिलाड़ियों को बधाई दी और अनुशासन के महत्व की जानकारी दी। जिला खेल समन्वयक गजेंद्र सिंह ने बताया इस प्रतियोगिता में अंदर 17 बालक बालिका तथा अंदर 19 बालक बालिका के चयनित खिलाड़ी हरिद्वार का प्रतिनिधित्व कर राज स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस अवसर पर आलोक कुमार, मनमोहन डबराल, रवि कुमार, अनुज कुमार , अरुण खरे समेत खेल प्रेमियों ने उपस्थित होकर अपना सहयोग दिया। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य सुबोध नेन प्रतिभागी खिलाड़ियों, सहयोगियों तथा खेल प्रेमियों का आभार प्रकट किया।

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा कहानी/कविता/निबन्ध प्रतियोगिता हेतु प्रविष्टियाँ आमंत्रित

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। युवा रचनाकारों (18 से 30 वर्ष) को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा कहानी/कविता/निबन्ध प्रतियोगिता हेतु प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जा रही हैं – कहानी/कविता/निबन्ध तीन प्रतियों में कम्प्यूटर टाइप ए4 आकार में भेजनी होगी। कहानी अधिकतम 2500 शब्द व कविता अधिकतम 500 शब्द (एक ओर टंकित) हो। निबन्ध ''पर्यावरण और हमारा दायित्व'' विषय पर केन्द्रित होगा, जो अधिकतम 2500 शब्द का (एक ओर टंकित) होगा। कहानीध्कविता भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों पर केन्द्रित होनी चाहिए।

कहानी/कविता/निबन्ध पर शीर्षक के अतिरिक्त लेखक का नाम व पता अंकित नहीं होना चाहिए। अलग पृष्ठ पर कहानी/कविता/निबन्ध के शीर्षक के साथ प्रतिभागी का नाम, पता, दूरभाष संख्या सहित हाईस्कूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। पूर्व में पुरस्कृत रचनाकार की प्रविष्टि उसी विधा में स्वीकार नहीं की जायेगी। प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 28 सितम्बर, 2024 है। प्रविष्टियाँ निदेशक, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन हिन्दी भवन, 6 महात्मा गांधी मार्ग, हजरत गंज, लखनऊ– 226001 के पते पर भेजी जायेगी। प्रविष्टि के लिफाफे पर कहानी/ कविता/ निबन्ध प्रतियोगिता लिखना अनिवार्य है। यह प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश के युवा रचनाकारों के लिए है। प्रथम पुरस्कार रु. 7,000, द्वितीय पुरस्कार रु. 5,000, तृतीय पुरस्कार रु. 4,000, सांत्वना पुरस्कार (संख्या–दो) रु. 2,000 निर्धारित है।

कैंट परिक्षेत्र युवा लखनऊ व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। लखनऊ व्यापार मंडल की कैंट परिक्षेत्र लखनऊ व्यापार मंडल एवं कैंट परिक्षेत्र युवा लखनऊ व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह के के पैलेस आलमबाग लखनऊ में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम के आयोजक और मुख्य वक्ता लखनऊ व्यापार मंडल के वरिष्ट महामंत्री पवन मनोचा ने बताया की कार्यक्रम की अध्यक्षता चेयरमैन राजेंद्र कुमार अग्रवाल,मुख्य अतिथि अध्यक्ष अमरनाथ मिश्रा,अति विशिष्ट अतिथि अनिल वीरमानी,कोषाध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता रहे । अध्यक्ष अमरनाथ मिश्रा और वरिष्ट महामंत्री पवन मनोचा ने चेयरमेन गुरजीत सिंह छाबड़ा,अध्यक्ष कपिल सिंह अरोड़ा,वरिष्ठ महामंत्री हरदीप सिंह,मुख्य वरिष्ट उपाध्यक्ष तरनजीत सिंह,कोषाध्यक्ष प्रबप्रीत सिंह सबरवाल, महामंत्री आशुतोष वर्मा ,सतीश आडवाणी हरमिंदर सिंह मिंदी,वरिष्ट उपाध्यक्ष गगनदीप सिंह, ,दमन सेठी भूपेंद्र सिंह पिंदा,सुधीर मल्होत्रा,प्रकाश चौरसिया,सुखपाल सिंह,उपाध्यक्ष मोहम्मद सेफ,इंद्रजीत सिंह,सतप्रीत सिंह,औरिंद्र सिंह,विकास सलूजा धीरज सुखवानी देवेंद्र सिंह गुरजीत सिंह कमलजीत सिंह अमृत पाल सिंह अंकित चौधरी आनंद सिंह सोनू सलूजा अनिल पंजवानी मंजीत सिंह भरत सुखवानी गुरदीप सिंह हैप्पी जोंटी बग्गा रितेश गोयल वरिष्ठ मंत्री सतविंदर सिंह मुकेश कारडा प्रचार मंत्री अमृती सिंह तजेंद्र पाल सिंह संगठन मंत्री मानिकजौहर मनी छाबड़ा अंकुश चौधरी संदीप छाबड़ा भूपेंद्र सिंह राजेश जुनेजा मल्टीमीडिया प्रभारी मानिक जोहार लीगल एडवाइजर प्रबजीत सिंह को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। चेयरमैन राजेंद्र अग्रवाल और अनिल वीरमानी ने चेयरमैन अन्नू पटेला,वाइज चेयरमैन मनमोहन सिंह मोनी,अध्यक्ष पद पर डॉ गिरीश कुमार,वरिष्ट महामंत्री सचिन चड्ढा,महामंत्री पद पर कुश अरोड़ा,रूबल सिंह,रोहित पंजवानी,वरिष्ट उपाध्यक्ष सचिन मल्होत्रा,उपाध्यक्ष हिमांशु सोनी,दीपक वेद,कोषाध्यक्ष रवींद्र सिंह (रवि),संघटन मंत्री राजा सिंह,संघटन मंत्री हैप्पी सिंह,संयुक्त मंत्री शिवम् गुलयानी,संयुक्त मंत्री आदित्य दुआ,मीडिया प्रभारी बँटी,और कपिल यादव को शपथ सिलाई । मुख्य अतिथि अमरनाथ मिश्र जी ने कहा आज जो हमारे बीच कैंट परिषेत्र की टीम बैठी है यह व्यापारियों के लिए 24 घंटे तट पर रहेगी कैंट परिषेत्र के व्यापारियों के हित की लड़ाई लखनऊ व्यापार मंडल के साथ यह सभी योद्धा अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे और अपनी ताकत के साथ अपने व्यापार की रक्षा के लिए सदैव लड़ते रहेंगे।

मुख्य वक्ता वरिष्ठ महामंत्री पवन मनोचा जी ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए कहा कि कैंट परिक्षेत्र के गठन की प्रक्रिया बहुत टाइम से चल रही थी आज हमने अनुभव के साथ युवा जोश की टीम की सरंचना की है मेरी कोशिश थी कैंट विधानसभा के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक बाजार ां अनुभव और जोश जैसे नाका,गणेशगंज,चारबाग कृष्णानगर,आलमबाग,टेढ़ीपुलिया,कानपुर रोड हो या मोहवाइया सबको जोड़ने का प्रयास किया जाए आज हम अपनो को शपथ दिला रहे इस संकल्प के साथ कि ये दौड़ रुकेगी नहीं अभी हमे कैंट विधानसभा में कई नई इकाइयों का गठन भी करना है अब हम फ्लाइंग स्क्वैट का भी गठन जल्द ही करेंगे क्षेत्र के हर व्यापारी की एक पुकार पर टीम उपलब्ध रहेगी । लखनऊ व्यापार मंडल के सचेतक अनिल वरमानी जी ने कहा कि कैंट पर क्षेत्र लखनऊ व्यापार मंडल की नई टीम जो गठित हुई है वह लखनऊ व्यापार मंडल को और ऊंचाइयों पर पहुंचने का कार्य करेगी। लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष एवं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजेंद्र कुमार अग्रवाल जी ने कहा कि हम सब के बीच बैठे हुए व्यापारी भाइयों हम सभी को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है हम सब व्यापारी एकजुट होकर किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं हम सब पहले व्यापारी हैं इसलिए हमें राजनीतिक पार्टियों के चक्कर नहीं लगते हैं हम सब लोग अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे कभी–कभी यह होता है कि कोई भी मुद्दा छोटी–छोटी राजनैतिक पार्टिया ले लेती हैं हम सभी को आधार बनाकर वह अपनी राजनीति को चमकते रहते हैं हमें उसे चक्रव्यूह में नहीं फसना है हम सभी को राजनीतिक पदों की लालसा नहीं रखनी चाहिए उसको त्याग देना चाहिए हम सब व्यापारी हैं और व्यापार करते हैं इसलिए हम सभी को व्यापारिक समस्याएं स्वयं मालूम है हमें अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है हम लोग राजनीति से अलग हटकर व्यापारियों के साथ खड़े होकर जो भी व्यापारिक समस्या होगी उसकी लड़ाई लड़ेंगे। लखनऊ व्यापार मंडल सदैव आपके साथ खड़ा रहेगा आज की शपथ लेने वाली टीम को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।

आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से लखनऊ व्यापार मंडल के चेयरमैन राजेंद्र कुमार अग्रवाल, सचेतक अनिल वरमानी,अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र वरिष्ठ महामंत्री पवन मनोचा,कोषाध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता,महामंत्री सुहेल हैदर अल्वी,जितेंद्र सिंह चौहान मनीष वर्मा,वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामकुमार वर्मा,वरिष्ट उपाध्यक्ष बबलू हबीब संदीप कांत राजन अजय पिपलानी विजय सनमुख त्रिलोक सिंह गौतम आहूजा अरविंद चौबे निर्मल सिंह लखनऊ महिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष निहारिका सिंह युवा अध्यक्ष मनीष गुप्ता वरिष्ठ महामंत्री सुमित गुप्ता, प्रियंक गुप्ता जितेंद्र प्रसाद कनौजिया,सुरेश कुमारी के साथ कैंट पर क्षेत्र के सैकड़ो व्यापारी प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मेदांता हास्पिटल, लखनऊ ने हासिल की 100 सफल ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी की उपलब्धि

मृत्युंजय प्रताप सिंह

लखनऊ। क्षेत्र के प्रमुख हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर, मेदांता हॉस्पिटल, लखनऊ ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हॉस्पिटल के ब्रेस्ट कैंसर विभाग की स्थापना के बाद से पिछले 18 महीनों में यहां सफलतापूर्वक 100 ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी की गई हैं। यह उपलब्धि अस्पताल की इस घातक बीमारी से लड़ रहे मरीजों को विश्वस्तरीय देखभाल प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इन सर्जरी में सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, ब्रेस्ट रि–शेपिंग या ऑन्कोप्लास्टी, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन और विशेषज्ञ डॉक्टरों वाले ट्यूमर बोर्ड द्वारा मरीज के लिए सर्वोत्तम इलाज के तरीकों पर चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण रही है। हॉस्पिटल द्वारा दी जाने वाली उन्नत सर्जिकल तकनीकें और चिकित्सा, ऑन्कोलॉजिस्ट और रेडियेशन टीम की विशेषज्ञता के कारण मरीजों को इलाज के बेहतर परिणाम मिल सके हैं। अस्पताल ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक व्यापक इलाज की सुविधा प्रदान करता है, जो प्रत्येक मरीज की विशेष जरूरतों के अनुसार तय की जाती है। शुरुआती स्टेज के इलाज में ब्रेस्ट–प्रिजर्विंग ऑपरेशन और सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी शामिल हैं, जो सर्जरी की जटिलताओं को कम करने के साथ–साथ कैंसर का प्रभावी ढंग से इलाज करती हैं। स्क्रीनिंग से पता चले प्रारंभिक स्तर के कैंसर, जब ट्यूमर का फैलाव अधिक नहीं होता है, ऐसे मरीजों के लिए, मेदांता लखनऊ एडवांस्ड सर्जरी जैसे वायर गाइडेड एक्ससिजन की सुविधा प्रदान करता है। जिन मरीजों को अपने ब्रेस्ट को सुरक्षित रखना है, ऐसे मरीजों के लिए अस्पताल ब्रेस्ट रि–शेपिंग या ऑन्कोप्लास्टी में विशेषज्ञता रखता है, जो ट्यूमर को हटाते हुए ब्रेस्ट की प्राकृतिक रूप–रंग को बनाए रखता है। इसके अलावा, मेदांता लखनऊ ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी भी प्रदान करता है, जिससे मरीजों को अपना आत्मविश्वास और शरीर की छवि पुनः प्राप्त करने में मदद मिलती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को होने वाले पारिवारिक कैंसर मामलों के लिए हॉस्पिटल हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर काउंसलिंग, जांच और उपचार के विकल्प शामिल करता है ताकि ऐसे कैंसर का समय से पता लगाकर उसका इलाज किया जा सके। ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करने वाली टीम युवा महिलाओं को गर्भधारण की क्षमता को बचाए रखने (ओवम की क्रायोफ्रीजिंग करने) और ब्रेस्ट को सुरक्षित रखने के लिए सही परामर्श और सलाह देती है, ताकि इलाज के दौरान उनकी प्रजनन क्षमता और ब्रेस्ट का स्वरूप प्रभावित न हो। मेदांता लखनऊ की ब्रेस्ट कैंसर देखभाल का एक महत्वपूर्ण पहलू ट्यूमर बोर्ड चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी है। ये मल्टीस्पेशलिटी मीटिंग्स विभिन्न विशेषज्ञों के साथ चर्चा करने के लिए होती हैं, ताकि प्रत्येक मरीज के लिए उसके हिसाब से इलाज की प्रक्रिया तय की जा सके। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इलाज के दौरान मरीज की जरूरतों का सम्मान करते हुए कम से कम क्षति पहुंचे और सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त हो।

डॉ. अमित अग्रवाल, कैंसर केयर, एंडोक्राइन और ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के डायरेक्टर, और डॉ. रोमा प्रधान, एसोसिएट डायरेक्टर, मेदांता हॉस्पिटल, लखनऊ ने टीम की इन उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त किया। डॉ. अग्रवाल ने कहा, "100 ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी की उपलब्धि हमारे मरीजों की देखभाल के प्रति हमारी अडिग प्रतिबद्धता और बेहतरीन उपचार प्रदान करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमने 30 से 79 साल के मरीजों का सफल इलाज किया है, जो हमारी विभिन्न तरह के इलाज की जरूरतों वाले मरीजों को अच्छे से इलाज प्रदान करने की क्षमता का प्रमाण है। डॉ. राकेश कपूर, मेडिकल डायरेक्टर, मेदांता हॉस्पिटल ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के मायने समझाते हुए कहा, "100 सफल ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी का लक्ष्य प्राप्त करना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है जो हमारी टीम की विशेषज्ञता और समर्पण का प्रमाण है। हमारी प्रतिबद्धता एडवांस्ड तकनीकों और मल्टी–डिसिप्लिनरी दृष्टिकोण को एक साथ लाने की है, जो यह सुनिश्चित करती है।

100 Successful

व्हाट्सएप एकाउंट हैक करने में युवक व पांच नाबालिग पकड़े

फर्रूखाबाद, संवाददाता। लोगों के व्हाट्सएप एकाउंट हैक कर अमेरिका की एक वेबसाइट पर डाटा भेजने के मामले में पुलिस ने एक युवक व पांच नाबालिगों को पकड़ लिया है। वेबसाइट से एक एकाउंट हैक करने पर इन लोगों को 24 घंटे में छह रुपये मिलते थे। एसपी आलोक कुमार प्रियदर्शी ने पुलिस लाइन के सभागार में बताया कि नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर निवासी कांग्रेस जिलाध्यक्ष शकुंतला देवी ने मोबाइल हैक करने का मुकदमा कराया। इसमें आरोप लगाया कि उनका व जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट नवाबगंज निवासी चालक मनोज कुमार का व्हाट्सएप एकाउंट हैक कर यह लोग गोपनीय सूचनाएं लीक कर रहे हैं। एसओ आमोद सिंह, साइबर थाने के दरोगा सुबोध यादव ने गांव सोना जानकीपुर निवासी रितेश व पांच नाबालिगों को पकड़ लिया। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि अमेरिका की वाहो वेबसाइट पर एक व्यक्ति के व्हाट्सएप एकाउंट को 24 घंटे के लिए हैक करने पर छह रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनको मिलते थे। उसी लालच में हम लोगों ने गांव के कई लोगों के मोबाइल कुछ देर के लिए मांगकर उनका व्हाट्स एप एकाउंट हैक कर डाटा वेबसाइट पर भेज देते थे। यह काम पिछले कई महीनों से कर रहे थे। एसपी ने बताया कि इस मामले में एक युवक व पांच नाबालिग पकड़े गए हैं। अन्य के बारे में भी पता लगाया जा रहा है।

युवक की गोली मारकर हत्या, शव सरकारी नलकूप पर फेंका, चेहरे पर मिले चोट के निशान

मेरठ, संवाददाता। मेरठ के पल्लवपुरम थानाक्षेत्र में दुल्हैड़ा के सरकारी नलकूप से थोड़ी दूरी युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यहां आनंदपाल के खेत के पास हत्या कर शव को फेंक दिया। घटनास्थल और युवक की हालत को देखकर लग रहा है कि उसने मौत से पहले बहुत संघर्ष किया है और हत्यारोपी ने उसकी साथ मारपीट भी की है। युवक ने सफेद शर्ट, ब्लू जींस और ब्रांडेड जूते पहन रखे हैं। सीधे हाथ में राखी भी बंधी हुई है। शव मिलने के बाद ग्रामीणों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। युवक की दो गोली मारकर हत्या की गई है। पल्लवपुरम थाना प्रभारी मुन्नेश सिंह ने बताया कि बुधवार सुबह दुल्हैड़ा स्थित सरकारी नलकूप से थोड़ी दूरी पर दुल्हैड़ा निवासी आनंदपाल के खेत के किनारे पर एक युवक का शव पड़ा होने की जानकारी मिली।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। युवक के चेहरे पर चोट के निशान मिले। गले पर भी निशान हैं और दोनों हाथ पर मिट्टी भी लगी हुई है। पूरा शरीर खून से लथपथ है। हत्यारों ने एक गोली सीने में और एक गोली पेट में गोली मारी है। पुलिस ने ग्रामीणों को मौके पर बुलाया। ग्रामीणों ने युवक के शव की पहचान करने का प्रयास किया, लेकिन शव की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को मोर्चरी के लिए भेज दिया।

समृद्ध घर से लग रहा युवक

युवक के शव को लेकर ग्रामीणों में तरह तरह की चर्चा बनी हुई हैं। उसके पहनावे को देखकर लग रहा है कि वह किसी समृद्ध घर से है। युवक के चेहरे पर बड़ी दाढ़ी है, जूते व जींस भी ब्रांडेड पहन रखी है। पुलिस शव की पहचान को लेकर सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुट गई है।

संक्षिप्त खबरें

पंखे के करंट से किशोरी की मौत

बांदा, संवाददाता। पंखे में आ रहे करंट से किशोरी की मौत हो गई। पंखा चालू करते समय हादसा हुआ। कालिंजर थाना क्षेत्र के गिर धरपुर गांव निवासी सुनैना राजपूत (16) शनिवार की दोपहर घर में पंखा चालू करने के लिए गई थी। तभी पंखे में आ रहे करंट से वह अचेत हो गई। परिजन उसे लेकर सीएचसी नरैनी पहुंचे। वहां से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। यहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

भाई सोनू ने बताया कि वह 11वीं में राजकीय इंटर कॉलेज कालिंजर में पढ़ती थी। पिता शारदा प्रसाद लकवाग्रस्त हैं। भाई ने बताया कि कस्बे में एक फेस नहीं आ रहा था। इस पर लाइनमैन ने गांव की घरेलू बिजली लाइनों को 11 हजार लाइन से जोड़ दिया था। इस कई घरों के उपकरण भी फुंक गए। कालिंजर थानाध्यक्ष रामदिनेश तिवारी ने बताया कि करंट से मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।

रंजिश में बाइक सवार राज मिस्त्री को डंडों से पीटा, रुपये छीने

बांदा, संवाददाता। रंजिश के चलते बाइक सवार दो लोगों को तीन बाइकों पर सवार छह लोगों ने घेर लिया। एक युवक को डंडों से पीटकर घायल कर दिया। दूसरे को धमका दिया। घायल युवक के जेब में पड़े एक लाख 65 हजार रुपये छीन लिए। दूसरे युवक के तीन हजार व मोबाइल ले गए। पुलिस ने पुत्री की तहरीर पर चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। तिंदवारी थाना क्षेत्र के सिंघौली गांव निवासी लाखन (40) गांव के ही पवन कुमार (28) के साथ तिंदवारी में मकान निर्माण के लिए गए थे। लाखन राजमिस्त्री है। दोनों शनिवार की रात तिंदवारी से लौट रहे थे। सिंघौली गांव के बाहर तीन बाइकों पर सवार छह लोग आए। हाथों में फावड़े का डंडा लिए थे। लाखन की बाइक में डंडा मारकर गिरा दिया और उसको घेरकर डंडों से पीट दिया। उसके सिर, हाथ, पैर में चोटें आईं। पवन ने बचाने का प्रयास किया तो उसे धमका दिया। हमलावरों ने लखन के पास से मकान निर्माण का एक लाख 65 हजार रुपये भी छीन लिया। पवन से भी तीन हजार रुपये और मोबाइल छीन लिए। घायल लाखन ने बताया कि हमलावरों में से एक को पहचान लिया है। पुरानी रंजिश के चलते उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। थाना इंस्पेक्टर राजेंद्र राजावत ने बताया कि पुत्री पूनम की तहरीर पर आरोपी कल्ली उर्फ रोहित, गणेश, महेश, अनिल व कुछ अज्ञात पर मारपीट की रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

फंदे पर लटका मिला युवक का शव, हत्या का आरोप, जांच

घाटमपुर, संवाददाता। घाटमपुर के जगदीशपुर गांव में बुधवार की शाम नलकूप की झोपड़ी में एक युवक का शव फंदे पर लटका मिला। परिजनों ने युवक के एक दोस्त पर हत्या कर शव फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेसिंक टीम को बुलाकर जांच पड़ताल की। जगदीशपुर गांव निवासी इंद्रपाल कुरील (48) खेती किसानी कर परिवार का भरण पोषण करता था। घर पर पत्नी राजकुमारी, बेटा सनी (11) व तीन बेटियां 19 वर्षीय शालू, 17 वर्षीय शीलू, 15 वर्षीय रिचा है। इंद्रपाल कुरील का शव बुधवार की शाम नलकूप में बनी झोपड़ी में भंदे पर लटकता मिला। परिजनों ने गांव में रहने वाले इंद्रपाल के एक दोस्त पर हत्याकर शव झोपड़ी में फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि दोनों में कुछ दिनों पहले विवाद भी हो चुका है। थाना प्रभारी पीके सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। परिजनों के आरोप की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि एक साल पहले मृतक के छोटे भाई ने भी आत्महत्या की थी।

चाचा ने होटल के कमरे में नाबालिग भतीजी से किया दुष्कर्म

महोबा, संवाददाता। महोबा जिले में रिश्तों को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है। सगे चाचा ने बहाने से होटल में ले जाकर नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म किया। किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी चाचा के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी 14 वर्षीय किशोरी ने महोबा कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि सात अगस्त को उसके चाचा उसे बहाने से छतरपुर मध्यप्रदेश ले गए थे। जहां रात होने पर होटल में रुकने की बात कही। आरोप लगाया कि रात के समय होटल के कमरे में चाचा ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

उधारी के रुपये मांगने पर पीटा, मुकदमा दर्ज

अलीगढ़, संवाददाता। बगांव नगला जंगली ऊर्फ गिलहटा निवासी एक व्यक्ति ने अपने रिश्तेदार पर उधार के रुपये मांगने पर पिटाई करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। न्यायालय के आदेश पर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। राजवीर सिंह ने बताया कि उसने अपने बेटे सुभाष की शादी प्रीति पुत्री शीशपाल सिंह निवासी नगला जंगली उर्फ गिलहटा के साथ की थी। आरोप है कि पुत्रवधू के पिता शीशपाल सिंह, रामकुमार उर्फ रामू, श्याम व सुंदर पुत्र शीशपाल सिंह ने अगस्त 2023 में पचास हजार रुपये उधार लिए थे। छह माह बाद रकम वापस देने का वादा किया था।

बेटे ने फावड़े से काटकर मां की बेरहमी से की हत्या

शामली, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में मंगलवार रात को एक युवक ने अपनी सोती हुई मां की फावड़े से काटकर हत्या कर दी। कुरैशी मोहल्ले में मंगलवार रात्रि करीब साढे तीन बजे बेटे ने मां साजो (65) पर फावड़े से वार कर हत्या कर दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक सोबान को हिरासत में ले लिया। आरोपी मानसिक रूप से बीमार बताया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक लंबे समय से बीमार था और पिछले चार दिनों से उसका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ था। मंगलवार रात्रि में बारह बजे आरोपी युवक अपने हाथो में फावड़ा लेकर निकला और बारी–बारी से मोहल्ले और पड़ोसियों के घरों पर फावडे से वार किए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक ने सड़क पर चलने वाली कारों पर भी उसने वार कर शीशे तोड़ दिए, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक व परिजनों को समझा बुझाकर चली गई। रात्रि करीब तीन बजकर 21 मिनट पर आरोपी युवक ने सोती हुई मां पर फावडेह्य से वार करते हुए उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि मृतका के मुंह पर कई वार किए हैं। एएसपी संतोष कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर जांच कराई गई। आरोपी युवक पुलिस की हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है।

हत्या के बाद पुलिस से भिड़ गया आरोपी, सीसीटीवी में कैद

मां की हत्या की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घर के बाहर से पुलिसकर्मियों ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन आरोपी पुलिसकर्मियों से ही भिड़ गया। पुलिसकर्मियों के साथ भी हाथापाई कर दी। पास में ही लगे सीसीटीवी में भी आरोपी मारपीट करते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिसकर्मी भी उसे पीट रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार, मंगलवार की रात में भी जब युवक ने मोहल्ले में खड़ी कार और मकानों में फावडेह्य से वार किए थे तो पुलिस मौके पर पहुंची थी। उस समय भी आरोपी पुलिसकर्मियों से भिड़ गया था। हालांकि, पुलिस आरोपी को पुलिस चौकी ले गई थी। बाद में ग्रामीणों के कहने पर युवक को रात में ही छोड़ दिया गया था। उसने वापस जाकर मां की हत्या कर डाली।

हैलट के बर्न वार्ड में खुलेगा प्रदेश का पहला स्किन बैंक

कानपुर, संवाददाता। कानपुर में हैलट के निर्माणाधीन बर्न वार्ड में स्किन बैंक खोलने की भी कवायद शुरू हो गई है। देहदानियों के शरीर की त्वचा यहां सुरक्षित की जा सकेगी। यह प्रदेश का पहला स्किन बैंक होगा। चूंकि पार्थिव शरीर से निकली त्वचा बर्न रोगियों के जख्मों के लिए सबसे अच्छे ड्रेसिंग मैटीरियल का काम करती है। इससे जख्म जल्दी भरते हैं। ऐसे में सौ फीसदी तक जले रोगियों का भी जीवन बचाया जा सकता है। युग दधीचि देहदान संस्थान ने त्वचा दान के लिए भी मुहिम शुरू कर दी है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभागाध्यक्ष और सीनियर प्लास्टिक सर्जन डॉ. प्रेमशंकर ने बताया कि हैलट में उच्चीकृत बर्न वार्ड का काम इसी साल पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही स्किन बैंक खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सौ फीसदी जले रोगियों के लिए दान में मिलने वाली त्वचा जीवनदायिनी होती है। दक्षिण भारत में स्किन बैंक खुले हुए हैं। इससे रोगियों की जान बचती है। देश का पहला स्किन बैंक 1972 में वाडिया चिल्ड्रेंस हॉस्पिटल मुंबई में खुला था। वहीं, युग दधीचि देहदान संस्थान के प्रमुख मनोज सेंगर ने स्किन बैंक के संबंध में मेडिकल कॉलेज प्रबंधन से बात की है। संस्थान मेडिकल कॉलेज के एनॉटमी विभाग को पार्थिव शरीर और नेत्र रोग विभाग को कार्निया दान कराता है। उन्होंने बताया कि देहदानियों के नेत्र के साथ उनकी त्वचा भी दान कराई जाएगी। पार्थिव देह से त्वचा उतारने में 15 मिनट से आधा घंटा लगता है।

त्वचा का रिजेक्शन नहीं होता, ब्लड ग्रुप की भी दिक्कत नहीं

डॉ. प्रेमशंकर ने बताया कि पार्थिव देह की त्वचा की पतली पर्त इपी डर्मिस, डर्मिस निकाली जाती है। यह ड्रेसिंग मैटीरियल की तरह काम करती है। इससे किसी तरह के रिजेक्शन की दिक्कत नहीं होती है। किसी भी ब्लड ग्रुप के पार्थिव शरीर की त्वचा किसी को लगाई जा सकती है। बर्न रोगियों के जख्मों पर त्वचा न होने से शरीर का फ्लुइड निकलता रहता है। इसमें प्रोटीन भी निकल जाता है। त्वचा की पर्त लगाने से द्रव्य बाहर नहीं निकल पाता। जख्म भरने लगता है। दो सप्ताह में रोगी की अपनी त्वचा बनने लगती है और ऊपर से ड्रेसिंग मैटीरियल के रूप में लगाई गई दान की त्वचा पपड़ी बनकर निकल जाती है। ऊपर से लगाई गई त्वचा दो सप्ताह तक जिंदा रहती है। देहदानी के निधन के आठ घंटे के अंदर त्वचा की पर्त निकाल ली जाती है।

क्या होता है स्किन बैंक

स्किन बैंक भी ब्लड बैंक की तरह होता है। यहां त्वचा को एक शीशी में भरकर मानइस तापमान में रखा जाता है। बैंक में तीन से पांच साल तक त्वचा सुरक्षित रखी जा सकती है। रखने से पहले त्वचा में संक्रमण आदि की भी जांच की जाती है। स्किन बैंक का काम जल्द शुरू किया जाएगा। त्वचा की पर्त लगाने से बर्न रोगियों के जख्मों में संक्रमण नहीं होता है। इसके अलावा फ्लूइड नहीं निकलता। दो सप्ताह में रोगियों को ड्रेसिंग पर लाखों का खर्च आता है। त्वचा की पर्त लगाने से खर्च में भी बचत होगी। 17 अगस्त को जयपुर में हुए अंगदान, देहदान सेमिनार में प्रदेश से मैंने प्रतिनिधित्व किया था। जयपुर में स्किन बैंक चल रहा है। उसी तरह के स्किन बैंक प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में खोले जाने की जरूरत है। इस संबंध में जीएसवीएम के प्राचार्य डॉ. संजय काला से भी बात की। मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजा है। देहदान और नेत्रदान के साथ त्वचा दान भी कराया जाएगा।

शस्त्र लाइसेंस संबंधी सभी आवेदन आनलाइन होंगे

कानपुर, संवाददाता। कानपुर में शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण और ट्रांसफर कराने के लिए अब कलक्ट्रेट के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने शस्त्र संबंधी सभी आवेदन ऑनलाइन करने के आदेश जारी किए हैं। जिले में 39 हजार से अधिक शस्त्र लाइसेंस हैं। वर्ष 2018 में असलहा लाइसेंस फर्जीवाड़ा होने के बाद शुरू हुई एसआईटी जांच अभी तक फंसी हुई है। एसआईटी ने जांच करने के बाद अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी। पांच साल से अभी तक कोई भी नया शस्त्र लाइसेंस नहीं बना है। शस्त्र अनुभाग के पास नवीनीकरण छोड़कर कोई काम नहीं है। ये काम भी एडीएम सिटी, तहसील संबंधी एसडीएम और एसीएम करते हैं। अन्य जिलों से कानपुर आने वाले करीब 300 लाइसेंस ट्रांसफर भी नहीं हो रहे हैं। करीब 400 से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस धारकों की मौत हो चुकी है। उनके परिजन शस्त्र लाइसेंस का विरासत कराने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। रोजाना शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण कराने और ट्रांसफर न करने की शिकायतों को सुनकर जिलाधिकारी परेशान हो गए। बुधवार को जनता दर्शन के दौरान शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण, ट्रांसफर न करने की शिकायतें पहुंचने के बाद बुधवार को डीएम नाराज हो गए। उन्होंने असलहा बाबू को मौके पर बुलाकर फटकार लगाई और कहा कि आज के बाद कोई भी ऑफ लाइन आवेदन नहीं लिया जाएगा। सभी आवेदन ऑनलाइन कराने के निर्देश दिए।

करीब 1080 असलहा लाइसेंस हुए सरेंडर

एसआईटी जांच के चक्कर में असलहा विभाग के सभी काम ठप पड़े हैं। एसआईटी जांच शुरू होने से अब तक 1080 असलहा लाइसेंस लोगों ने सरेंडर कर दिए हैं। परेशान होकर लोग खुद ही असलहा लाइसेंस सरेंडर कर रहे हैं। शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण, नए बनवाने और स्थानांतरण के लिए सारे आवेदन अब ऑनलाइन स्वीकृत किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन अब नहीं लिए जाएंगे। सभी का समय पर निस्तारण किया जाएगा।

नगर निगम में आवेदकों को समय से नहीं मिल रहा जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र

पोर्टल के धीमी गति से चलते आ रही परेशानी – डा0 राम मणि शुक्ला

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

Infinix SMART5

अयोध्या। इस समय नगर निगम कार्यालय से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।यहां पर जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र लेने वाले दर्जनों आवेदकों ने एक सुर में बताया कि हम लोग इस कार्यालय पर एक से दो महीने पहले से फार्म जमा कर चुके हैं। परंतु अब तक उन्हें जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल सका है।उन आवेदकों का कहना है कि आज किसी भी सरकारी व गैर सरकारी कार्य मे जन्म प्रमाण पत्र को लगाना पड़ता है,ठीक वही हालात मृत्यु प्रमाण पत्र के लिये है।क्योंकि मृत्यु प्रमाण पत्र जारी न होने के चलते कुछ आवश्यक कार्य रुके हुए हैं।यहां पर जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र लेने आने वाले आवेदकों ने बताया कि जिसके चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।अगर यहां पर तैनात कर्मियों की मानें तो यह समस्या पिछले दो से तीन महीने पहले से बनी हुई है। जिसका मुख्य कारण इसका साफ्टवेयर अपडेट होने के चलते पोर्टल प्रभावित है।उन्होंने बताया कि एक दिन 60 से 70 यहां तक कि 100 से ऊपर तक आवेदन जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के बनने के लिए आ रहे हैं। जिसके चलते अब तक हजारों आवेदन जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनने के लिए कार्यालय में जमा हुए है।परंतु पोर्टल न चलने के चलते जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं जारी हो पा रहा है।इस संबंध में नगर निगम में तैनात स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राम मणि शुक्ला ने बताया कि इस समय साफ्टवेयर अपडेट हो रहा है।जिसके चलते इस समय इसका पोर्टल काफी धीमा चल रहा है। जिसके चलते यह समस्या उत्पन्न हो रही है।उन्होंने बताया कि उनकी कोशिश यही रहती है कि अधिक से अधिक जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र शीघ्र से शीघ्र आवेदकों को मिले। जिसके चलते जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले आवेदकों का कार्य न रुके।

318 करोड़ के सीवर प्रोजेक्ट में धांधली, इंजीनियरों को लगी फटकार... थमाया गया नोटिस तलब किया लखनऊ

आगरा, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के आगरा में 318 करोड़ रुपये के वेस्टर्न जोन सीवरेज प्रोजेक्ट में हुई धांधलियों पर जल निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर समेत इंजीनियरों को फटकार लगाई गई है। दो दिन के दौरे पर आगरा आए प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने जल निगम के अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। सुधार के लिए उन्होंने 15 दिन का वक्त दिया है और उसके बाद रिपोर्ट लेकर इंजीनियरों को लखनऊ तलब किया है। सोमवार को पार्षदों ने आवास विकास कॉलोनी, पश्चिमपुरी, जगदीशपुरा, किशोरपुरा, लोहामंडी में नई बिछाई सीवर लाइन के उफनने, चोक हो जाने और कनेक्शन न करने की शिकायत की थी। इस पर मंगलवार को प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने जल निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर स्वतंत्र सिंह को सार्वजनिक रूप से फटकारा और चेतावनी दी कि वेस्टर्न जोन सीवरेज प्रोजेक्ट में की गई गड़बड़ियों को 15 दिन में सुधार दें। कॉलोनियों में उन्हें सीवर लाइन को नालियों से जोड़ देने, घरों के कनेक्शन न करने की शिकायतें मिली थीं। जल निगम के चीफ इंजीनियर आर के पंकज से उन्होंने कहा कि अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण लें। उन्होंने फतेहाबाद रोड पर सफाई व्यवस्था ठीक न मिलने पर सेनेटरी इंस्पेक्टर योगेंद्र कुशवाह को भी कारण बताओ नोटिस और चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव अमृत अभिजात को सेक्टर 4 रोड के घरों के कनेक्शन दिखाए गए, लेकिन 24 बार धंसी सड़क पर नहीं ले गए। इसी तरह बोदला रोड, मारुति एस्टेट, श्याम नगर पर वेस्टर्न जोन सीवर प्रोजेक्ट में बिछाई नई सीवर लाइन के चोक होने और सीवर बहने की जगह नहीं ले गए, पर पार्षदों ने जल निगम के इंजीनियरों की पोल खोल ही दी। मंगलवार को हुई बैठक में उन्होंने मनीषा प्रोजेक्ट्स की लाइनों के जुड़े न होने, घरों के कनेक्शन न होने, नालियों में डालने पर एतराज जताया और प्रोजेक्ट मैनेजर स्वतंत्र सिंह पर नाराजगी जताई।

60 वर्ष के ऊपर के साहित्यकारों को सरकार द्वारा 50 हजार रुपए तक के चिकित्सा सहायता हेतु प्रस्ताव आमंत्रित

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान लखनऊ द्वारा साहित्यकार कल्याण कोष योजना के अन्तर्गत विषय आर्थिक स्थितिग्रस्त या रुग्ण साहित्यकारों को जिनकी वार्षिक आय (समस्त स्रोतों से) रुपये पांच लाख तक है तथा 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है।

उन्हें अधिकतम रुपये पचास हजार तक अनावर्तक चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन के साथ तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र एवं चिकित्सक का प्रमाणपत्र, दो साहित्यकारों की संतुतियाँ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

उक्त योजना की नियमावली एवं आवेदन पत्र का प्रारुप संस्थान कार्यालय से किसी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। संस्थान में प्रार्थना पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 21 सितम्बर, 2024 है। योजनाओं के विवरण के वितरण एव प्रार्थना पत्र का प्रारूप संस्थान की वेबसाइट www. uphindisansthan.in पर भी उपलब्ध है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी मे. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 – 7007415808, 9628325542, 9415034002
RNI NO - UPHIN/2022/86937
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।